

7-8 Apr. 2024



डेली करंट अफेयर्स

GEO IAS

SOURCES



THE HINDU



The Indian EXPRESS
JOURNALISM OF COURAGE



PIB
Press Information Bureau



AAP
Aam Aadmi Party



live mint



THE
FINANCIAL
EXPRESS



ET
ECONOMIC TIMES.COM

Date: 7-8 Apr. 2024

Important News Articles

1. इंडोनेशियाई प्रतिनिधिमंडल ने अग्रणी योजनाओं को अपनाने हेतु भारत का दौरा किया -
2. अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच AUKUS के विस्तार को लेकर चर्चा - द हिंदू
3. उत्पाद शुल्क नीति मामला: कोर्ट ने के कविता की जमानत याचिका खारिज की - इंडियन एक्सप्रेस
4. लोकसभा चुनाव: सुविधा पोर्टल पर 73,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए- टाइम्स ऑफ इंडिया
5. जलवायु संकट नागरिकों के जीवन के अधिकार को प्रभावित करता है: सुप्रीम कोर्ट - इंडियन एक्सप्रेस
6. अनावश्यक रूप से कॉम्प्लेक्स GST में तत्काल सुधार की आवश्यकता: केलकर - द हिंदू
7. विदेशी निवेशक: वर्ष 2023 में भारत में बड़ी वैश्विक वीसी फर्मों में 80% गिरावट
8. प्याज व्यापारी UAE को कम कीमत पर प्याज के निर्यात से नाराज - द हिंदू

Editorials, Gists and Explainers

9. यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज (UHC) सिस्टम - द हिंदू
10. सार्वजनिक हित में प्राइवेट हेल्थ केयर में सुधार की आवश्यकता - द हिंदू

Quick Look

1. लैब-विकसित मिनीब्रेन
2. मंगल पांडे
3. सतपुला बांध
4. ओशनिक नीनो इंडेक्स

महत्वपूर्ण समाचार लेख

सामान्य अध्ययन II

1. इंडोनेशियाई प्रतिनिधिमंडल ने अग्रणी योजनाओं को अपनाने हेतु भारत का दौरा किया - द हिंदू

प्रासंगिकता: केंद्र और राज्यों द्वारा आबादी के कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का प्रदर्शन; इन कमजोर वर्गों की सुरक्षा और बेहतरी के लिए गठित तंत्र, कानून, संस्थाएं और निकाय।

प्रीलिम्स टेक अवे

- मिड-डे मील योजना

समाचार :

- **इंडोनेशिया,** हाल ही में संपत्र चुनावों के बाद, राष्ट्रपति के तहत नई सामाजिक-आर्थिक पहल शुरू करना चाहता है और मिड-डे मील योजना और डिजिटल समावेशन में सर्वोत्तम गतिविधियों को अपनाने के लिए भारत से संपर्क किया है।

मिड-डे मील योजना

- **भारत का विशाल स्कूल लंच कार्यक्रम:** यह कार्यक्रम, जिसे अब प्रधानमंत्री पोषण योजना कहा जाता है, अपनी तरह का दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है।
- यह कक्षा 1 से 8 तक के लाखों बच्चों को उनकी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना हर दिन गर्म भोजन प्रदान करता है।
- **बच्चों की मदद करने का एक लंबा इतिहास:** यह कार्यक्रम वर्ष 1925 में वंचित बच्चों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ शुरू हुआ था।
- यह वर्ष 1995 में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम बन गया और इसमें कुछ नाम परिवर्तन किए गए।
- **स्वस्थ भविष्य के लिए लक्ष्य:** कार्यक्रम का लक्ष्य अधिक से अधिक बच्चों, विशेषकर वंचित परिवारों के बच्चों का स्कूल में दाखिला कराना और उन्हें स्कूल में रहने के लिए प्रेरित करना है।
- यह भूख से लड़ने, बच्चों के पोषण में सुधार और विभिन्न जातियों के बीच सामाजिक संपर्क को बढ़ावा देने के लिए भी काम करता है।
- **इसे साकार करने हेतु मिलकर काम करना :** प्रत्येक राज्य विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रम के प्रबंधन के लिए समितियाँ गठित करता है।
- संघीय सरकार राज्यों के साथ लागत साझा करती है, कुछ क्षेत्रों में अधिक योगदान होता है।

2. अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच AUKUS के विस्तार को लेकर चर्चा - द हिंदू

प्रासंगिकता: भारत के हितों, भारतीय प्रवासियों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव।

प्रीलिम्स टेक अवे

- AUKUS
- मानचित्र आधारित प्रश्न

समाचार:

- **अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया** अपने **AUKUS सुरक्षा समझौते** में नए सदस्यों को लाने पर बातचीत शुरू करने के लिए तैयार हैं क्योंकि वाशिंगटन चीन के खिलाफ निवारक के रूप में जापान को शामिल करने पर जोर दे रहा है।

मुख्य बिंदु

- ये पहले स्तंभ का विस्तार करने पर विचार नहीं कर रहे हैं, जिसे ऑस्ट्रेलिया में परमाणु-संचालित हमलावर पनडुब्बियों को वितरित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- **वर्ष 2021** में तीन देशों द्वारा गठित AUKUS, इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में चीन की बढ़ती ताकत के खिलाफ पीछे हटने के उनके प्रयासों का हिस्सा है।
- **चीन ने AUKUS समझौते** को खतरनाक बताया है और चेतावनी दी है कि इससे क्षेत्रीय हथियारों की होड़ को बढ़ावा मिल सकता है।

ऑक्स ग्रुपिंग

- यह ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस (AUKUS) के बीच इंडो-पैसिफिक के लिए एक त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी है जिस पर वर्ष 2021 में हस्ताक्षर किए गए थे।

- इस व्यवस्था का मुख्य आकर्षण अमेरिकी परमाणु पनडुब्बी प्रौद्योगिकी को ऑस्ट्रेलिया के साथ साझा करना है।
- इसका इंडो-पैसिफिक झुकाव इसे दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामक कार्रवाइयों के खिलाफ गठबंधन बनाता है।
- इसमें तीन देशों के बीच बैठकों और जुड़ाव की एक नई वास्तुकला के साथ-साथ उभरती प्रौद्योगिकियों (अनुप्रयुक्त एआई, कांटम प्रौद्योगिकियों और समुद्र के नीचे की क्षमताओं) में सहयोग शामिल है।

3. उत्पाद शुल्क नीति मामला: कोर्ट ने के कविता की जमानत याचिका खारिज की - इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप और उनके डिजाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे।

समाचार:

- धन शोधन निवारण अधिनियम (**PMLA**) में कड़े जमानत प्रावधानों में महिलाओं के लिए एक अपवाद है।
- दिल्ली की एक अदालत दिल्ली उत्पाद शुल्क घोटाला मामले में इस आधार पर जमानत के लिए भारत राष्ट्र समिति नेता की याचिका पर फैसला करने के लिए तैयार है।

प्रीलिम्स टेकअवे

- PMLA
- UAPA

PMLA में जमानत का प्रावधान

- धारा 45 मनी लॉडिंग के आरोप में जमानत का प्रावधान करती है।
- कानून में यह प्रावधान, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (**UAPA**) में कड़े जमानत मानक की तरह, आरोपी पर यह साबित करने की जिम्मेदारी डालता है कि जमानत मांगते समय उसके खिलाफ कोई प्रथम दृष्ट्या मामला नहीं है।
- हालाँकि, जमानत मानक में एक महत्वपूर्ण अपवाद है।
- कानून कहता है, "बशर्ते कोई व्यक्ति, जो सोलह वर्ष से कम उम्र का है या महिला है या बीमार या अशक्त है, उसे जमानत पर रिहा किया जा सकता है, यदि विशेष अदालत ऐसा निर्देश दे।"
- यह अपवाद महिलाओं और नाबालिगों के लिए भारतीय दंड संहिता के तहत छूट के समान है।

कानूनी मिसाल क्या है?

- HC** ने कहा कि **PMLA** या संविधान एक घरेलू महिला, एक व्यवसायी महिला या एक राजनीतिक व्यक्ति के बीच अंतर नहीं करता है।

4. लोकसभा चुनाव: सुविधा पोर्टल पर 73,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए- टाइम्स ऑफ इंडिया

प्रासंगिकता: कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली - सरकार के मंत्रालय और विभाग; दबाव समूह और औपचारिक/अनौपचारिक संघ और राज्य व्यवस्था में उनकी भूमिका।

प्रीलिम्स टेकअवे

- सुविधा पोर्टल
- भारतीय चुनाव आयोग (ECI)

समाचार:

- चुनाव आयोग ने रविवार को कहा कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद से उसके सुविधा पोर्टल पर विभिन्न प्रचार गतिविधियों के लिए अनुमति मांगने के लिए **73,000** से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं।

सुविधा पोर्टल

- इसे स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावों के लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कायम रखने के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए भारतीय चुनाव आयोग (ECI) द्वारा विकसित किया गया है।
- इसने चुनाव अवधि के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से अनुमति और सुविधाओं के अनुरोध प्राप्त करने और उन पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया।
- यह फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सिद्धांत पर पारदर्शी रूप से विभिन्न प्रकार के अनुमति अनुरोधों को पूरा करता है।

- राजनीतिक दल और उम्मीदवार किसी भी समय, कहीं से भी अनुमति अनुरोध आँनलाइन जमा कर सकते हैं।
- ऑफलाइन सबमिशन विकल्प उपलब्ध हैं।
- यह रैलियों के आयोजन, अस्थायी पार्टी कार्यालय खोलने, घर-घर जाकर प्रचार करने, वीडियो वैन, हेलीकॉप्टर, वाहन परमिट प्राप्त करने, पर्चे बांटने की अनुमति प्रदान करता है।
- यह एक मजबूत आईटी प्लेटफॉर्म द्वारा समर्थित है, जिसका प्रबंधन विभिन्न राज्य विभागों के नोडल अधिकारियों द्वारा किया जाता है।
- इसमें एक सहयोगी ऐप भी है जो आवेदकों को वास्तविक समय में उनके अनुरोधों की स्थिति को ट्रैक करने में सक्षम बनाता है।
- इसके अलावा, पोर्टल पर उपलब्ध अनुमति डेटा चुनाव व्यय की जांच के लिए एक मूल्यवान संसाधन के रूप में कार्य करता है, जो चुनावी प्रक्रिया में अधिक जवाबदेही और अखंडता में योगदान देता है।

सामान्य अध्ययन III

5. जलवायु संकट नागरिकों के जीवन के अधिकार को प्रभावित करता है: सुप्रीम कोर्ट - इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन।

समाचार:

- एक महत्वपूर्ण फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने "जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ अधिकार" को शामिल करने के लिए अनुच्छेद 14 और 21 के दायरे का विस्तार किया है।

प्रीलिम्स टेकअवे

- अनुच्छेद 21
- अनुच्छेद 14

मुख्य बिंदु

- "संविधान के अनुच्छेद 48A में प्रावधान है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और देश के जंगलों और वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।"
- अनुच्छेद 51A के खंड (g) में कहा गया है कि जंगलों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और जीवित प्राणियों के प्रति दया रखना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा।
- अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को मान्यता देता है जबकि अनुच्छेद 14 इंगित करता है कि सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण प्राप्त होगा।
- ये अनुच्छेद स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ अधिकार के महत्वपूर्ण स्रोत हैं।

सरकारी नीति

- बावजूद इसके कि सरकारी नीति और नियम-कायदे जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को पहचान रहे हैं और इससे निपटने की कोशिश कर रहे हैं।
- स्वास्थ्य का अधिकार (जो अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक हिस्सा है) वायु प्रदूषण, वेक्टर जनित बीमारियों में बदलाव, बढ़ते तापमान, सूखा, फसल की विफलता के कारण खाद्य आपूर्ति में कमी, तूफान और बाढ़ जैसे कारकों के कारण प्रभावित होता है।
- अदालत ने बताया कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट (गीगावाट) की स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता (बड़ी पनबिजली को छोड़कर) हासिल करना है, एक लक्ष्य जो स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के लिए देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, और भविष्य का लक्ष्य 2030 तक 450 गीगावॉट स्थापित क्षमता है।
- नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश न केवल इन ताल्कालिक पर्यावरणीय चिंताओं का समाधान करता है, बल्कि बहुत सारे सामाजिक-आर्थिक लाभ भी देता है।

6. अनावश्यक रूप से कॉम्प्लेक्स GST में तत्काल सुधार की आवश्यकता: केलकर - द हिंदू

प्रासंगिकता: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधन जुटाने, वृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे।

समाचारः :

- भारत के टैक्स सुधारों के प्रमुख वास्तुकार और तेरहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय केलकर ने देश की अगली सरकार से "अनावश्यक रूप से कॉम्प्लेक्स" वस्तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था में तत्काल सुधार करने का आह्वान किया है।
- जैसे कि 12% की एकल टैक्स दर पर स्विच करना और स्थानीय सरकारों और नगर निगमों के साथ राजस्व साझा करना।

प्रीलिम्स टेक्स अवधि

- GST
- GST परिषद

तेरहवें वित्त आयोग विजय केलकर की सिफारिश

- जुलाई 2017 में लागू अप्रत्यक्ष टैक्स के लिए सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था GST परिषद के लिए एक स्वतंत्र सचिवालय के निर्माण पर भी विचार किया गया।
- चूंकि सचिवालय को संचालित करने वाली केंद्र सरकार की वर्तमान व्यवस्था को राज्यों द्वारा समस्याग्रस्त माना जा सकता है।
- टैक्स दरें निर्धारित करना "बड़े पैमाने पर राजस्व तटस्थित बनाए रखने के उद्देश्य से" जैसा कि भारत द्वारा किया गया है, "प्रति-उत्पादक" है

एकल GST दर की आवश्यकता

- वर्तमान GST धोखाधड़ी की उत्पत्ति GST दरों की संरचना में निहित है, क्योंकि GST की उच्च दरें धोखेबाजों के लिए टैक्स से बचने को आकर्षक बनाती हैं।
- सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी स्तरों के साथ राजस्व को समान रूप से साझा करते हुए 12% की एकल GST दर जल्द से जल्द पेश की जाए।
- एकल दर और सरल GST या वैट कानून वाले देश कर राजस्व को अनुकूलित करने और टैक्स विवादों को कम करने में सफल रहे हैं
- GST या वैट प्रणाली वाले देशों में से 80% ने एकल टैक्स दर का विकल्प चुना है, जिसमें सिंगापुर, न्यूजीलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और जापान शामिल हैं।
- यह कहते हुए कि भारत में एकल GST दर "एक अधूरा लक्ष्य" है, उन्होंने याद दिलाया कि 13वें वित्त आयोग द्वारा "GST बहस में बहुत पहले" 12% की एकल दर की सिफारिश की गई थी।
- हाइड्रोकार्बन जैसे कुछ अवगुण वस्तुओं पर कार्बन टैक्स जैसे अतिरिक्त गैर-वैट-योग्य टैक्स के साथ एकल GST दर की शुरूआत का क्रांतिकारी सुधार अब आवश्यक है।

GST को स्थानीय निकायों के साथ साझा करें:

- अनुभवी अर्थशास्त्री ने GST राजस्व को संविधान के 73वें और 74वें संशोधन द्वारा बनाई गई सरकार के तीसरे स्तर के साथ साझा करने की भी वकालत की है।
- तीसरे स्तर के साथ GST की समान हिस्सेदारी हमारी शहरी सरकारों के वित्तीय आधार को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र और शासन को मजबूत करने में काफी मदद करेगी।
- इसे सक्षम करने के लिए, हमें सबसे पहले सरकार के तीसरे स्तर के लिए समेकित निधि बनाने के लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी।

7. विदेशी निवेशक: वर्ष 2023 में भारत में बड़ी वैश्विक वीसी फर्मों में 80% गिरावट

प्रासंगिकता: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधन जुटाने, वृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे।

समाचार:

- भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम की तथाकथित फंडिंग विंटर के बीच, एक्सेल, पीक एक्सवी पार्टनर्स, टाइगर ग्लोबल और सॉफ्टबैंक जैसे बड़े विदेशी निवेशकों का निवेश वर्ष 2023 में औसतन **80 प्रतिशत** तक गिर गया।

मुख्य बिंदु

- बावजूद इसके, उनमें से कई का कहना है कि वे **भारतीय बाजार** को लेकर बहुत उत्साहित हैं और इस साल अपने निवेश में बढ़ोतरी करना चाह रहे हैं।
- पिछले दो वर्षों में, ये बड़ी वैश्विक उद्यम पूंजी (VC) कंपनियां भारतीय बाजार से बाहर निकलती दिख रही हैं।
- यह विशेष रूप से चिंताजनक है क्योंकि विदेशी निवेश भारत में कुल फंडिंग का एक बड़ा हिस्सा है।

प्रभाव:

- सर्दियों की फंडिंग के साथ, स्टार्ट-अप ऐसे उपायों का सहारा लेते हैं जो उन्हें अपनी कार्यशील पूंजी बचाने में मदद करते हैं, क्योंकि निवेशकों से फंडिंग की उम्मीदें न्यूनतम होती हैं।
- फर्म की स्थिरता बढ़ाने के लिए विज्ञापन व्यय, पूंजीगत व्यय और विस्तार योजनाओं को रोक दिया जाता है।
- केवल फर्म के अस्तित्व के लिए आवश्यक व्यय ही किया जाता है और अनावश्यक खर्चों को सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव कदम उठाए जाते हैं।

8. प्याज व्यापारी UAE को कम कीमत पर प्याज के निर्यात से नाराज - द हिंदू

प्रासंगिकता: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधन जुटाने, वृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे।

प्रीलिम्स टेकअवे

- अप्रत्याशित लाभ

समाचार:

- प्याज के निर्यात पर लंबे समय तक प्रतिबंध के बीच, किसान और व्यापारी इस बात से नाराज हैं कि संयुक्त अरब अमीरात (UAE) जैसे बाजारों में सरकार द्वारा अनुमति दी गई कुछ शिपमेंट को कौड़ियों के दाम पर बेचा गया है, जबकि वैश्विक कीमतें बढ़ गई हैं, जिससे चुनिंदा आयातकों को अप्रत्याशित मुनाफा हो रहा है।

UAE आयातकों को फायदा

- ये निर्यात विशेष रूप से सहकारिता मंत्रालय के तहत सरकारी स्वामित्व वाली संस्था नेशनल को-ऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (NCEL) के माध्यम से किया जा रहा है।
- निर्यातकों को बताया गया कि निर्यात सरकार-से-सरकार के आधार पर किया जा रहा है, आयातक देश नामांकित आयातकों को कोटा आवंटित करता है।
- ऐसे निर्यात के लिए खरीद एग्रीबाजार पोर्टल पर ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के माध्यम से की जा रही है।

आयातक-निर्यातक नेक्सस

- इस नेक्सस के कारण भारतीय किसानों को उनकी खाद्य फसल का वास्तविक मूल्य नहीं मिल पा रहा है

अप्रत्याशित लाभ

- यह लाभ में अचानक वृद्धि को संदर्भित करता है, जो आमतौर पर किसी अप्रत्याशित घटना या परिस्थिति के कारण होता है।
- इस तरह के मुनाफे आम तौर पर ऐतिहासिक मानदंडों से काफी ऊपर होते हैं और मूल्य वृद्धि या आपूर्ति की कमी जैसे कारकों के कारण हो सकते हैं जो या तो प्रकृति में अस्थायी होते हैं या लंबे समय तक चलने वाले होते हैं।
- अप्रत्याशित मुनाफा आम तौर पर पूरे उद्योग क्षेत्र द्वारा प्राप्त किया जाता है, लेकिन यह किसी व्यक्तिगत कंपनी या व्यक्ति को भी मिल सकता है।
- अप्रत्याशित लाभ उत्पन्न होने के कारणों में बाजार संरचना में अचानक बदलाव, सरकार का एक कार्यकारी आदेश, एक अदालत का फैसला या व्यापार नीति में एक नाटकीय बदलाव शामिल हैं।

एडिटोरियल, जिस्ट, एक्सप्लेनेर

9. यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज (UHC) सिस्टम - द हिंदू

प्रासंगिकता: स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।
समाचार:

- **यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज (UHC)** वित्तीय कठिनाई के बिना व्यापक, उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच का प्रतीक है।
- **यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज (UHC)** यह सुनिश्चित करता है कि लोगों को जब भी और जहां भी आवश्यकता हो, देखभाल मिले।
- इसमें स्वास्थ्य संवर्धन से लेकर रोकथाम, उपचार, पुनर्वास और उपशामक देखभाल तक आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं की संपूर्ण निरंतरता शामिल है।

मुख्य बिंदु

- 12 दिसंबर 2012 को, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव का समर्थन किया जिसमें देशों से UHC की दिशा में प्रगति में तेजी लाने का आग्रह किया गया।
- भारत में, वर्ष 2011 में योजना आयोग को सौंपी गई उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट में 12वीं योजना (वर्ष 2012-17) के दौरान स्वास्थ्य के लिए सार्वजनिक वित्तपोषण को भारत के सकल घरेलू उत्पाद के 2.5% तक बढ़ाने के सरकारी इरादे को रेखांकित किया गया था।
- देश की आर्थिक वृद्धि इस वृद्धि को संभव बनाती है।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 अपने लक्ष्य के रूप में अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के उच्चतम संभव स्तर की प्राप्ति को बताती है, जो UHC लक्ष्य के साथ सेरेखित है।

स्वास्थ्य का अधिकार

- भारत में बुनियादी स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार के लिए संवैधानिक प्रावधान का अभाव है।
- हालाँकि, संविधान के भाग IV में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत स्वास्थ्य के अधिकार के लिए एक आधार प्रदान करते हैं।
- संविधान का अनुच्छेद 39 (e) राज्य को श्रमिकों के स्वास्थ्य को सुरक्षित करने का निर्देश देता है।
- अनुच्छेद 42 काम और मातृत्व राहत की उचित और मानवीय स्थितियों पर जोर देता है।
- अनुच्छेद 47 राज्य पर पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का कर्तव्य रखता है।
- संविधान न केवल राज्य को सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का आदेश देता है, बल्कि अनुच्छेद 243G के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए पंचायतों और नगर पालिकाओं को भी अधिकार देता है।
- यह देखते हुए कि स्वास्थ्य एक राज्य का विषय है और UHC नीति की परिकल्पना राष्ट्रीय स्तर पर की गई है, कार्यान्वयन पर चर्चा की आवश्यकता है।
- भारत में एक बड़ी प्रवासी आबादी है, अंतर-राज्य प्रवासी श्रमिकों की कुल संख्या लगभग 41 मिलियन थी (जनगणना 2011) और कुल प्रवासन दर 28.9% थी। (आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, 2020-21)।
- UN -हैबिटेट/विश्व बैंक के अनुसार, 49% आबादी शहरी मलिन बस्तियों में रहती है, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और पहुंच सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
- UHC नीति के दो महत्वपूर्ण घटकों प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करना और जेब से खर्च को कम करना ध्यान केंद्रित करने की मांग करता है।
- UHC कार्यान्वयन के साथ चुनावी जनादेश को सेरेखित करने के लिए, राजनीतिक नेताओं को निम्नलिखित सुझावों पर विचार करना चाहिए।

सुझाव

- अपनी जेब से होने वाले खर्च को कम करने के लिए प्रतिपूर्ति प्रक्रियाओं को सरल बनाना।
- भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में नकद हस्तांतरण और प्रतिपूर्ति के डिजाइन को प्रवासी और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए अनुकूलन की आवश्यकता है।
- हमें स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली डैशबोर्ड को सार्वजनिक और निजी दोनों प्रणालियों के साथ एकीकृत करने और शहरी संदर्भ में भाषा बाधाओं और विविधता को ध्यान में रखते हुए बेहतर सूचना प्रणाली सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
- निर्बाध रेफरल प्रणालियों के साथ शहरी और उप-शहरी क्षेत्रों में समुदाय-आधारित प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को लागू करना।

- हमें प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल स्तर पर सेवाओं के एकीकरण को बढ़ावा देने, स्वास्थ्य देखभाल के अनुवर्ती और अनुपालन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

10. सार्वजनिक हित में प्राइवेट हेल्प केयर में सुधार की आवश्यकता - द हिंदू

प्रासंगिकता: स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

समाचार:

- कोविड-19** महामारी के दौरान इलाज की मांग करते समय लाखों भारतीयों को दर्दनाक अनुभवों से गुजरना पड़ा।
- इसने हमारी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में बदलाव की दो पूरक धाराओं, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को विनियमित करने की तत्काल आवश्यकता को दृढ़ता से रेखांकित किया।
- भारतीय संदर्भ में, स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार की कोई भी पहल निजी स्वास्थ्य सेवा को प्रभावित किए बिना पूरी नहीं होगी, जो देश में स्वास्थ्य सेवा उपयोग का लगभग 70% हिस्सा है।

मुख्य बिंदु

- वर्ष 2024 फोर्ब्स की अरबपतियों की सूची में 200 भारतीय शामिल हैं।
- विनिर्माण के बाद, वह उद्योग जो आज भारत में अरबपतियों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या (36) का योगदान देता है, फार्मास्यूटिकल्स सहित स्वास्थ्य सेवा है।
- भारत में निजी स्वास्थ्य सेवा को उच्च मुनाफा कमाने की अनुमति है, क्योंकि यह अपर्याप्त रूप से विनियमित है और अक्सर मरीजों से अत्यधिक शुल्क वसूलती है।
- यह सेटिंग हाल ही में प्रकाशित जन स्वास्थ्य अभियान के 18 सूत्री पीपुल्स हेल्प मेनिफेस्टो में निहित नीतिगत सिफारिशों की प्रासंगिकता को रेखांकित करती है।

पारदर्शिता, दरों का मानकीकरण

- निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता शायद भारत में सभी व्यावसायिक सेवाओं के बीच अद्वितीय हैं, क्योंकि उनकी सेवाओं की दरें आम तौर पर सार्वजनिक डोमेन में पारदर्शी रूप से उपलब्ध नहीं होती हैं।
- क्लिनिकल प्रतिष्ठान (केंद्र सरकार) नियम, 2012 निर्दिष्ट करते हैं कि सभी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को अपनी दरें प्रदर्शित करनी चाहिए और समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित मानक दरों पर शुल्क लेना चाहिए।
- हालाँकि, इन कानूनी प्रावधानों के लागू होने के 12 साल बाद भी, आश्वर्यजनक रूप से इन्हें अभी तक लागू नहीं किया गया है।
- अतार्किक स्वास्थ्य देखभाल हस्तक्षेपों को रोकने के लिए मानक प्रोटोकॉल लागू करना भी आवश्यक है, जिन्हें वर्तमान में व्यावसायिक विचारों के कारण व्यापक पैमाने पर प्रचारित किया जाता है।
- उपचार पद्धतियों को तर्कसंगत बनाने और अत्यधिक चिकित्सा प्रक्रियाओं पर अंकुश लगाने से न केवल कई निजी अस्पतालों द्वारा वसूले जाने वाले अत्यधिक बिल में कमी आएगी, बल्कि रोगियों के लिए स्वास्थ्य देखभाल परिणामों में भी उल्लेखनीय सुधार होगा।

मरीजों के अधिकार लागू करें

- इनमें प्रत्येक रोगी को उनकी स्थिति और उपचार के बारे में बुनियादी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार, और देखभाल की अपेक्षित लागत और मदबद्ध बिल शामिल हैं;
- भारतीय संदर्भ में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने वर्ष 2018 में मरीजों के अधिकारों और जिम्मेदारियों का एक सेट तैयार किया।
- इसके अलावा, निजी अस्पतालों से संबंधित गंभीर शिकायतों वाले मरीजों के लिए न्याय सुनिश्चित करने में मेडिकल काउंसिल जैसे मौजूदा तंत्र की विफलता को देखते हुए

महाविद्यालयों के व्यावसायीकरण पर नियंत्रण रखें

- व्यावसायीकृत निजी मेडिकल कॉलेजों को नियंत्रित करने की तत्काल आवश्यकता है, विशेष रूप से यह अनिवार्य करना कि उनकी फीस सरकारी मेडिकल कॉलेजों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- इसके अलावा, चिकित्सा शिक्षा का विस्तार व्यवसायिक निजी संस्थानों के बजाय सार्वजनिक कॉलेजों पर केंद्रित होना चाहिए।

निष्कर्ष

- राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को स्वतंत्र, बहु-हितधारक समीक्षा और सुधार की आवश्यकता है, इन आलोचनाओं को ध्यान में रखते हुए कि इस निकाय में विविध हितधारकों के प्रतिनिधित्व का अभाव है, इसमें निर्णय लेने की प्रक्रिया अत्यधिक केंद्रीकृत है, और चिकित्सा शिक्षा के आगे व्यावसायीकरण की ओर रुझान है।
- आज, सभी राजनीतिक दलों को इन परिवर्तनों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, जबकि नागरिक के रूप में हमें दृढ़ता से इनकी मांग करनी चाहिए। यह वर्ष 2024 में भारत में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने का एक उपयुक्त तरीका होगा।

फैक्ट फटाफट

1. लैब-विकसित मिनीब्रेन

- इन्हें वैज्ञानिक रूप से मस्तिष्क ऑर्गेनोइड के रूप में जाना जाता है, लेकिन अक्सर इन्हें "मिनीब्रेन" कहा जाता है और ये पूर्ण आकार के मानव मस्तिष्क के लघु सरलीकृत मॉडल के रूप में काम करते हैं।
- वैज्ञानिक आम तौर पर स्टेम कोशिकाओं से मस्तिष्क ऑर्गेनोइड विकसित करते हैं, एक प्रकार की अपरिपक्व कोशिका जो किसी भी प्रकार की कोशिका को जन्म दे सकती है, चाहे रक्त, त्वचा, आंत या मस्तिष्क।
- ऑर्गेनोइड विकसित करने के लिए उपयोग की जाने वाली स्टेम कोशिकाएं या तो वयस्क मानव कोशिकाओं से या शायद ही कभी, मानव भ्रूण ऊतक से आ सकती हैं।
- वैज्ञानिक वयस्क कोशिकाओं को इकट्ठा करते हैं और फिर उन्हें स्टेम सेल जैसी स्थिति में लाने के लिए उन्हें रसायनों के संपर्क में लाते हैं। परिणामी स्टेम कोशिकाओं को "प्रेरित प्लुरिपोटेंट स्टेम कोशिकाएं" (iPSC) कहा जाता है, जिन्हें किसी भी प्रकार के ऊतक में विकसित किया जा सकता है।
- एक मिनीब्रेन को जन्म देने के लिए, वैज्ञानिक इन स्टेम कोशिकाओं को एक प्रोटीन युक्त मैट्रिक्स में एम्बेड करते हैं, एक ऐसा पदार्थ जो कोशिकाओं को विभाजित होने पर समर्थन देता है और एक 3D आकार बनाता है। वैकल्पिक रूप से, कोशिकाओं को एक भौतिक, 3D मचान के ऊपर उगाया जा सकता है।

2. मंगल पांडे

- उन्हें प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नायक माना जाता है, जिसे वर्ष 1857 का सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है।
- उनका जन्म 19 जुलाई, 1827 को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद के पास हुआ था।
- वर्ष 1849 में, पांडे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल हो गए और बैरकपुर में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फैट्री की 6वीं कंपनी में एक सिपाही के रूप में कार्य किया।
- ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध विद्रोह:
- उन्होंने जानवरों की चर्बी वाले कारतूसों को पेश करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया क्योंकि इससे सैनिकों की धार्मिक भावनाएं आहत होती थीं।
- विद्रोहियों का यह आंदोलन भारत के अन्य हिस्सों तक पहुंच गया और औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ बड़े पैमाने पर विद्रोह हुआ

3. सतपुला बांध

- सतपुला ('सत' का अर्थ है सात और 'पुल' का अर्थ है पुल का खुलना) का निर्माण सुल्तान मुहम्मद शाह तुगलक (1325-1351) के शासनकाल के दौरान किया गया था।
- इसे अरावली में पाए जाने वाले दिल्ली कार्ट्ज पथर का उपयोग करके बनाया गया था।
- इसे दिल्ली के चौथे शहर जहांपनाह की रक्षा दीवार के एक अभित्र अंग के रूप में विकसित किया गया था। बांध ने दो उद्देश्यों को पूरा किया: सिंचाई के लिए पानी का एक विश्वसनीय स्रोत प्रदान करना, और संभावित घुसपैठियों के खिलाफ रक्षा के रूप में कार्य करना।
- इसे उपयुक्त स्थलाकृति की पहचान करके विकसित किया गया था, यानी, एक बड़ा खुला मैदान जहां बड़ी समतल भूमि की सिंचाई के लिए पानी जमा किया जा सकता है। इसलिए, स्लुइस गेट और जलाशय वाली यह संरचना विकसित की गई।

- चूंकि सूफी संत नसीरुद्दीन महमूद (जिन्हें चिराग देहलवी के नाम से जाना जाता है) पास में रहते थे, लोगों का मानना था कि नहर के पानी में उपचार गुण हैं।

4. ओशनिक नीनो इंडेक्स

- यह मौसमी जलवायु पैटर्न के समुद्री हिस्से की निगरानी के लिए प्राथमिक संकेतक है जिसे अल नीनो-दक्षिणी दोलन या "ENSO" कहा जाता है।
- यह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के निकट, पूर्व-मध्य उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में 120° - 170° W के बीच चल रहे 3 महीने के औसत समुद्री सतह तापमान को ट्रैक करता है, और क्या वे औसत से अधिक गर्म या ठंडे हैं।
- +0.5 या उससे अधिक का सूचकांक मान अल नीनो को दर्शाता है और -0.5 या उससे कम का मान ला नीना को दर्शाता है।



प्रीलिम्स ट्रैक

Q1. निम्नलिखित युग्म पर विचार करें

- पोषण योजना: विद्यालय में मिड-डे मील उपलब्ध कराया गया
- पीएम मत्स्य सम्पदा योजना: मत्स्य पालन क्षेत्र के किसानों के लिए
- स्वामित्व योजना: ड्रोन की मदद से गांवों में संपत्तियों की मैपिंग

ऊपर दिए गए युग्मों में से कितने जोड़े सही हैं?

- केवल एक
- केवल दो
- सभी तीनों
- कोई नहीं

Q2. AUKUS ग्रुपिंग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

- यह ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका (AUKUS) के बीच इंडो-पैसिफिक के लिए एक त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी है जिस पर 2021 में हस्ताक्षर किए गए थे।
- भारत और जापान इसके पर्यवेक्षक सदस्य हैं
- इसका इंडो-पैसिफिक झुकाव इसे दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामक कार्रवाइयों के खिलाफ गठबंधन बनाता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

- केवल एक
- केवल दो
- सभी तीनों
- कोई नहीं

Q3. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

- मनी लांडिंग की रोकथाम के लिए संविधान में अलग से प्रावधान है
- गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA) में कड़े जमानत मानक, आरोपी पर यह साबित करने की जिम्मेदारी डालते हैं कि जमानत मांगते समय उनके खिलाफ कोई प्रथम दृष्ट्या मामला नहीं है।
- यदि कोई सोलह वर्ष से कम आयु का है या महिला है या बीमार या अशक्त है, तो उसे जमानत पर रिहा किया जा सकता है, यदि विशेष न्यायालय ऐसा निर्देश दे

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने गलत हैं?

- केवल एक
- केवल दो
- सभी तीनों
- कोई नहीं

Q4. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

- स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावों के लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कायम रखने के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए CERT-In द्वारा सुविधा पोर्टल विकसित किया गया है।
- यह फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सिद्धांत पर पारदर्शी रूप से विभिन्न प्रकार के अनुमति अनुरोधों को पूरा करता है।
- राजनीतिक दल और उम्मीदवार किसी भी समय, कहीं से भी अनुमति अनुरोध अँनलाइन जमा कर सकते हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

- केवल एक
- केवल दो
- सभी तीनों
- कोई नहीं

Q5. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

- "संविधान के अनुच्छेद 51 A में प्रावधान है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और देश के जंगलों और वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।
- अनुच्छेद 48A के खंड (G) में कहा गया है कि जंगलों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और जीवित प्राणियों के प्रति दया रखना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा।
- अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को मान्यता देता है

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

- केवल एक
- केवल दो
- सभी तीनों
- कोई नहीं

Q6. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

- भारतीयों के पास वर्तमान में 12% GST की एकल दर है
- GST राजस्व को संविधान के 73वें और 74वें संशोधन द्वारा बनाई गई सरकार के तीसरे स्तर के साथ साझा किया जाएगा।
- हाइड्रोकार्बन जैसी कुछ अवगुण वस्तुओं पर कार्बन कर जैसे कर अब लागू हैं

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही है/हैं?

- A. केवल एक
- B. केवल दो
- C. सभी तीनों
- D. कोई नहीं

Q7. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. आर्थिक मंदी की अवधि के कारण स्टार्टअप्स के लिए उद्यम पूँजी (वीसी) फंडिंग में कमी आ सकती है।
2. इन अवधियों के दौरान, स्टार्टअप को पूँजी जुटाने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है, जिससे उनकी विकास क्षमता में बाधा आ सकती है।
3. सरकार स्टार्टअप्स पर आर्थिक मंदी के प्रभाव को कम करने के लिए ऋण गारंटी या टैक्स छूट जैसी नीतियां लागू कर सकती हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही है/हैं?

- A. केवल एक
- B. केवल दो
- C. सभी तीनों
- D. कोई नहीं

Q8. अप्रत्याशित लाभ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. अप्रत्याशित लाभ तब उत्पन्न होता है जब कंपनियां अपने नियंत्रण से परे बाहरी कारकों के कारण मुनाफे में अचानक और महत्वपूर्ण वृद्धि का अनुभव करती हैं।
2. अप्रत्याशित मुनाफ़ा — अक्सर 'अप्रत्याशित घटनाओं से जुड़ा होता है जैसे कमोडिटी की कीमतों में वृद्धि, सरकारी नीति में बदलाव या प्राकृतिक आपदाएँ।
3. सरकार इन अप्रत्याशित लाभ का एक हिस्सा हासिल करने के लिए अप्रत्याशित लाभ टैक्स लगा सकती है, जिसका उद्देश्य ऐसी स्थितियों के दौरान धन का पुनर्वितरण करना या मुनाफाखोरी को हतोत्साहित करना है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही है/हैं?

- A. केवल एक
- B. केवल दो
- C. सभी तीनों
- D. कोई नहीं

Q9. विलनिकल प्रतिष्ठान (केंद्र सरकार) नियम, 2012

1. नियम, 2012 भारत में चिकित्सा सुविधाओं के कामकाज को विनियमित करने के लिए अधिनियमित किए गए थे।
2. ये नियम प्रस्तावित सेवाओं के प्रकार और बिस्तर क्षमता के आधार पर नैदानिक प्रतिष्ठानों के पंजीकरण और वर्गीकरण के लिए एक प्रणाली स्थापित करते हैं।
3. नियम मानक उपचार दिशानिर्देशों का पालन करना और रोगियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड (EMR) के रखरखाव को अनिवार्य करते हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही है/हैं?

- A. केवल एक
- B. केवल दो
- C. सभी तीनों
- D. कोई नहीं

Q10. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

कथन I : स्वास्थ्य सातवीं अनुसूची के तहत संघ सूची में आता है लेकिन स्वास्थ्य नीतियों को लागू करने के लिए राज्य जिम्मेदार हैं

कथन II: संविधान न केवल राज्य को सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का आदेश देता है, बल्कि अनुच्छेद 243G के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए पंचायतों और नगर पालिकाओं को भी अधिकार देता है।

निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

- A. कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है
- B. कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है
- C. कथन I और कथन II दोनों सही हैं और कथन II कथन I की सही व्याख्या है
- D. कथन I और कथन II दोनों गलत हैं और कथन II कथन I का सही व्याख्या नहीं है

प्रीलिम्स ट्रैक उत्तर

उत्तर : 1 विकल्प C सही है

व्याख्या

- प्रधानमंत्री पोषण योजना -पीएम पोषण स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना के तहत, सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को एक गर्म पका हुआ भोजन प्रदान किया जाएगा।
- पीएम मत्स्य सम्पदा योजना- मत्स्य पालन क्षेत्र में किसानों के लिए राष्ट्रव्यापी कल्याणकारी उपाय। 2020-2024 की अवधि के लिए कार्यान्वयन के लिए ₹20,050 करोड़ (2023 में ₹220 बिलियन या अमेरिका \$2.8 बिलियन के बराबर) का अनुमानित आवंटन।
- स्वामित्व योजना- ड्रोन की मदद से गांवों में संपत्तियों की मैपिंग में मदद करना। इसका उद्देश्य संपत्ति पर विवादों को कम करने में मदद करना है। यह पोर्टल ग्रामीणों के लिए बैंक ऋण प्राप्त करना आसान बनाने में मदद करेगा। **अतः सभी विकल्प सही हैं**

उत्तर : 2 विकल्प B सही है

व्याख्या

- यह ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका (AUKUS) के बीच इंडो-पैसिफिक के लिए एक त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी है जिस पर 2021 में हस्ताक्षर किए गए थे।
 - इस व्यवस्था का मुख्य आकर्षण अमेरिकी परमाणु पनडुब्बी प्रौद्योगिकी को ऑस्ट्रेलिया के साथ साझा करना है।
 - इसका इंडो-पैसिफिक झुकाव इसे दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामक कार्रवाइयों के खिलाफ गठबंधन बनाता है।
 - इसमें तीन देशों के बीच बैठकों और जुड़ाव की एक नई वास्तुकला के साथ-साथ उभरती प्रौद्योगिकियों (अनुप्रयुक्त एआई, कांटम प्रौद्योगिकियों और समुद्र के नीचे की क्षमताओं) में सहयोग शामिल है।
- इसलिए कथन 1 और 3 सही हैं**

उत्तर : 3 विकल्प A सही है

व्याख्या

- मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 (PMLA) भारत की संसद का एक अधिनियम है जो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने और मनी लॉन्ड्रिंग से प्राप्त संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान करने के लिए बनाया गया है। **इसलिए कथन 1 गलत है**

- धारा 45 मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जमानत का प्रावधान करती है।
- कानून में यह प्रावधान, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA) में कड़े जमानत मानक की तरह, आरोपी पर यह साबित करने की जिम्मेदारी डालता है कि जमानत मांगते समय उसके खिलाफ कोई प्रथम दृष्ट्या मामला नहीं है।
- हालाँकि, जमानत मानक में एक महत्वपूर्ण अपवाद है।
- कानून कहता है, "बशर्ते कोई व्यक्ति, जो सोलह वर्ष से कम उम्र का है या महिला है या बीमार या अशक्त है, उसे जमानत पर रिहा किया जा सकता है, यदि विशेष अदालत ऐसा निर्देश दे।"
- यह अपवाद महिलाओं और नाबालिगों के लिए भारतीय दंड संहिता के तहत छूट के समान है। **अतः कथन 2 और 3 सही हैं**

उत्तर : 4 विकल्प B सही है

व्याख्या

- इसे स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावों के लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कायम रखने के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए भारत के चुनाव आयोग (ECI) द्वारा विकसित किया गया है। **इसलिए, कथन 1 गलत है।**
- इसने चुनाव अवधि के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से अनुमति और सुविधाओं के अनुरोध प्राप्त करने और उन पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया।
- यह फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सिद्धांत पर पारदर्शी रूप से विभिन्न प्रकार के अनुमति अनुरोधों को पूरा करता है। **अतः, कथन 2 और 3 सही हैं।**
- राजनीतिक दल और उम्मीदवार किसी भी समय, कहीं से भी अनुमति अनुरोध ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।

उत्तर : 5 विकल्प A सही है

व्याख्या

- "संविधान के अनुच्छेद 48 A में प्रावधान है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और देश के जंगलों और वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।

- अनुच्छेद 51A के खंड (G) में कहा गया है कि जंगलों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और जीवित प्राणियों के प्रति दया रखना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। **इसलिए, कथन 1 और 2 गलत हैं।**
- अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को मान्यता देता है जबकि अनुच्छेद 14 इंगित करता है कि सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण प्राप्त होगा। **इसलिए, कथन 3 गलत है।**

उत्तर : 6 विकल्प D सही है

व्याख्या

- सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी स्तरों के साथ राजस्व को समान रूप से साझा करते हुए 12% की एकल GST दर जल्द से जल्द पेश की जाए।
- एकल दर और सरल GST या वैट कानून वाले देश कर राजस्व को अनुकूलित करने और कर विवादों को कम करने में सफल रहे हैं।
- GST या वैट प्रणाली वाले देशों में से 80% ने एकल कर दर का विकल्प चुना है, जिसमें सिंगापुर, न्यूजीलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और जापान शामिल हैं।
- यह कहते हुए कि भारत में एकल GST दर "एक अधूरा लक्ष्य" है, उन्होंने याद दिलाया कि 13वें वित्त आयोग द्वारा "GST बहस में बहुत पहले" 12% की एकल दर की सिफारिश की गई थी।
- हाइड्रोकार्बन जैसे कुछ अवगुण वस्तुओं पर कार्बन कर जैसे अतिरिक्त गैर-वैट-संक्षम कराँ के साथ एकल GST दर की शुरूआत का क्रांतिकारी सुधार अब आवश्यक है।
- GST को स्थानीय निकायों के साथ साझा करें।
- अनुभवी अर्थशास्त्री ने GST राजस्व को संविधान के 73वें और 74वें संशोधन द्वारा बनाई गई सरकार के तीसरे स्तर के साथ साझा करने की भी वकालत की है। **अतः सभी कथन गलत हैं।**

उत्तर : 7 विकल्प C सही है

व्याख्या

- आर्थिक मंदी का तात्पर्य आर्थिक गतिविधियों में कमी की अवधि से है, जो अक्सर धीमी वृद्धि या सकल घरेलू उत्पाद में संकुचन की विशेषता होती है। इससे ये हो सकता है:

- निवेशकों का विश्वास कम होना: मंदी के दौरान निवेशक अधिक सतर्क हो जाते हैं, जिससे वे स्टार्टअप जैसे जोखिम भरे उपक्रमों में निवेश करने के लिए कम इच्छुक हो जाते हैं।
- सख्त ऋण शर्तें: बैंक ऋण देने में सख्त हो सकते हैं, जिससे स्टार्टअप के लिए ऋण प्राप्त करना कठिन हो जाएगा।
- स्टार्टअप्स पर प्रभाव: स्टार्टअप्स अक्सर विकास के लिए वीसी फंडिंग पर बहुत अधिक निर्भर होते हैं। फंडिंग में कमी के कारण हो सकते हैं।
- विकास में बाधा: स्टार्टअप्स को विस्तार योजनाओं को धीमा करने या यहां तक कि कर्मचारियों की छंटनी करने के लिए मजबूर किया जा सकता है।
- नवप्रवर्तन में मंदी: फंडिंग कम होने से अनुसंधान और विकास में निवेश सीमित हो सकता है, जिससे नवप्रवर्तन में बाधा आ सकती है।
- सरकारी हस्तक्षेप: सरकारें स्टार्टअप्स पर मंदी के प्रभाव को कम करने में भूमिका निभा सकती हैं।
- ऋण गारंटी: सरकार स्टार्टअप्स द्वारा लिए गए ऋणों के लिए गारंटी प्रदान कर सकती है, जिससे बैंकों के लिए जोखिम कम हो जाएगा और उन्हें ऋण देने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा।
- टैक्स में छूट: टैक्स में छूट कठिन समय के दौरान स्टार्टअप्स के लिए वित्तीय राहत प्रदान कर सकती है, जिससे उन्हें संसाधनों का संरक्षण करने और मुख्य संचालन पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिलती है। **तीनों कथन सही हैं।**

उत्तर : 8 विकल्प C सही है

व्याख्या

- अप्रत्याशित मुनाफ़ा अप्रत्याशित होता है और अक्सर बाहरी कारकों के कारण कंपनियों के मुनाफ़े में अस्थायी उछाल होता है। ये कारक आम तौर पर कंपनी के नियंत्रण से बाहर होते हैं और इसकी मुख्य व्यावसायिक रणनीतियों का परिणाम नहीं होते हैं।
- अप्रत्याशित लाभ के सामान्य कारणों में शामिल हैं:
- कमोडिटी की कीमत में उतार-चढ़ाव: तेल, खनिज, या अन्य वस्तुओं की कीमत में अचानक वृद्धि उन कंपनियों के मुनाफे को काफी बढ़ा सकती है जो उन संसाधनों का उत्पादन या व्यापार करते हैं।
- सरकारी नीतियां: सरकारी नीतियों में बदलाव, जैसे टैक्स कटौती या सब्सिडी, विशिष्ट उद्योगों के लिए अप्रत्याशित लाभ पैदा कर सकते हैं।

- प्राकृतिक आपदाएँ: प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले व्यवधान अस्थायी कमी पैदा कर सकते हैं, जिससे उन कंपनियों के लिए कीमतें बढ़ सकती हैं जो अभी भी आवश्यक सामान या सेवाएं प्रदान कर सकती हैं।
- अप्रत्याशित लाभ टैक्स इन अप्रत्याशित मुनाफों पर सरकार द्वारा लगाया जाने वाला एकमुश्त या अस्थायी कर है। इस टैक्स का उद्देश्य हो सकता है:
- राजस्व सृजन: सरकार कर राजस्व का उपयोग सामाजिक कार्यक्रमों या सार्वजनिक निवेशों के वित्तपोषण के लिए कर सकती है।
- **अतः सभी कथन सही हैं**

उत्तर : 9 विकल्प C सही है

व्याख्या

- क्लिनिकल प्रतिष्ठान (केंद्र सरकार) नियम, 2012, क्लिनिकल प्रतिष्ठान (पंजीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 के तहत तैयार किए गए नियमों का एक समूह है।
- स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता में सुधार: बुनियादी ढांचे, स्टाफिंग और चिकित्सा सुविधाओं द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के लिए न्यूनतम मानक स्थापित करके।
- रोगी की सुरक्षा सुनिश्चित करें: संक्रमण नियंत्रण, जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन और उचित रिकॉर्ड रखने पर नियमों के माध्यम से।
- पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना: सुविधाओं के पंजीकरण और वर्गीकरण को अनिवार्य करके, आसान निगरानी और शिकायत निवारण की अनुमति देना।

- पंजीकरण और वर्गीकरण: नैदानिक प्रतिष्ठानों को बिस्तर क्षमता, पेश की जाने वाली विशिष्टताओं और निष्पादित नैदानिक प्रक्रियाओं जैसे कारकों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। यह आवश्यक पंजीकरण के स्तर (अनंतिम या स्थायी) और लागू विशिष्ट नियमों को निर्धारित करता है।
- मानक उपचार दिशानिर्देश: नियमों के तहत केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा जारी उपचार दिशानिर्देशों का पालन करना आवश्यक है। इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य चिकित्सा पद्धतियों को मानकीकृत करना और साक्ष्य-आधारित देखभाल सुनिश्चित करना है।
- इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड (EMR): नियम मरीजों के लिए EMR के रखरखाव को प्रोत्साहित या अनिवार्य (सरकारी निर्देश के आधार पर) करते हैं। इससे बेहतर रिकॉर्ड रखने की सुविधा मिलती है, देखभाल समन्वय में सुधार होता है और पारदर्शिता बढ़ती है। **अतः सभी कथन सही हैं**

उत्तर : 10 विकल्प B सही है

व्याख्या

- संविधान न केवल राज्य को सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का आदेश देता है, बल्कि अनुच्छेद 243G के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए पंचायतों और नगरपालिकाओं को भी अधिकार देता है। **अतः, कथन 2 सही है**
- यह देखते हुए कि स्वास्थ्य एक राज्य का विषय है और UHC नीति की परिकल्पना राष्ट्रीय स्तर पर की गई है, कार्यान्वयन पर चर्चा की आवश्यकता है। **इसलिए, कथन 1 गलत है**



ABOUT US

GEO IAS is the best institute for civil services in India for providing top quality teaching and materials, offering you most optimum path for your success in Civil Services exam. Our aim is to provide quality training with an affordable fee structure. Our uniquely designed course make us the best institute for UPSC to crack the exam in one go. We have a dedicated team of experienced and young teachers and counsellors who make sure that every student who joins the institute, must get customized way of preparation which matches with student's learning style. The only institute of UPSC in India which has 3 AI enabled Mobile apps. We believe in Smart way of teaching and learning. The classes are available in offline as well as in online mode. We take the help of animation so that you may visualize the lectures. Unlimited tests for prelims and mains with solution in both form (Hard copy and soft copy). We have the set of 15 lac mcqs on each topic. We provide daily news analysis, Highlighted news paper and links of important Sansad TV shows. The institute has best success rate with more than 230 students have cleared the exam. HIGHEST RATED INSTITUTE as per GOOGLE, SULEKHA and JUST DIAL and the magazine on civil services



+91-9477560001 /002/005



info@geoias.com



BRANCH: Delhi Kolkata, Raipur, Patna |
HEAD OFFICE: 641, Ramlal Kapoor Marg,
Mukherjee Nagar, Delhi, 110009



www.geoias.com